JK Cement Ltd.
CIN: L17229UP1994PLC017199
Registered Office
Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P., India
+91-512-2371478 to 85 +91-512-2399854
shambhu.singh@jkcement.com
www.jkcement.com

21st May,2025

BSE Limited, Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 Scrip Code: 532644 (ISIN.INE823G01014) Through: BSE Listing Centre	The National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Scrip Code: JKCEMENT (ISIN.INE823G01014) Through: NEAPS

Dear Sir/Ma'am

Sub: Newspaper Insertion about dispatch of Notice/ Intimation prior to transfer of unclaimed/unpaid dividend and Equity Shares pertaining to Financial Year 2017-18.

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, as amended and in accordance with Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, transfer and Refund) Rules, 2016, we have sent Notice/ Intimations to the shareholders, requesting them to claim their unclaimed /unpaid dividends for the last seven years and the company has published advertisement in leading newspapers.

Please find enclosed the newspaper insertion about dispatch of Notice/ Intimations on 20.05.2025 which was published on Wednesday, May 21,2025 in the following newspapers and also uploaded on our website www.jkcement.com.

1.**Business Standard (English), All Editions**

2.Business Standard (Hindi), All Editions

3.Hindustan (Hindi), Kanpur Editions

Thanking you,
Yours faithfully,
For J.K. Cement ltd.

SHAMBHU SINGH
Digitally signed by SHAMBHU SINGH
Date: 2025.05.21 17:22:26 +05'30'

Shambhu Singh
Vice President & Company Secretary
M.No. FCS- 5836
Encl.: As above

Corporate Office
Prism Tower, 5th Floor, Ninaniya Estate,
Gwal Pahari, Gurugram, Haryana-122102
+0124-6919000
prismtower@jkcement.com
www.jkcement.com

JK SUPER CEMENT BUILD SAFE
JK SUPER STRONG BUILD SAFE
JK CEMENT WallMax White Cement Wall Putty
Manufacturing Units at :
Nimbahera, Mangrol, Gotan (Rajasthan) | Muddapur (Karnataka)
Jharli (Haryana) | Ujjain, Katni (M.P.) | Aligarh (U.P.) | Balasinor (Gujarat)

JK Cement Ltd.
CIN: L17229UP1994PLC017199
Registered Office
Kamla Tower, Kanpur - 208001, U.P., India
+91-512-2371478 to 85 +91-512-2399854
shambhu.singh@jkcement.com
www.jkcement.com

TALAT FATIMA HASAN
C/O M/S S K VOHRA & CO
CHARTERED ACCOUNTANT 32 REGAL BUILDING

NEW DELHI 110001

Date : 09/05/2025
Ref.No : 1
Folio No./DP-CLID : 402736
Shares : 19

Dear Shareholder,

Sub:- Transfer of shares relating to unclaimed dividend due and remained unpaid consecutively for last seven (7) financial years to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

We wish to inform you that as per the provisions of the Section 124(6) and other applicable Sections of the Companies Act, 2013 ('the said Act'), and Rules / Regulation framed there under all shares in respect of which a shareholder has not claimed dividend consecutively for the last 7 years, from F.Y. 2017-18 be transferred by the Company in favour of Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government.

As per our records, it appears that you have not encashed / claimed dividend warrants for the last 7 consecutive years commencing from the Financial Year 2017-2018 as under though relevant dividend warrants were posted to your recorded address.

Dividend Year	Dividend Warrant No.	Dividend Amount (Rs.)
2017-2018	643	190.00
2018-2019	512	190.00
2019-2020	477	142.50
2020-2021	438	285.00
2021-2022	224	285.00
2022-2023	1294	285.00
2023-2024	1965	380.00

The unclaimed dividend(s) up to Financial Year 2016-17 has already been transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), as required under Section 124(5) of the said Act.

Therefore, the relevant shares are required to be transferred to the IEPF account.

You are requested to claim the unclaimed dividends from Financial Year 2017-18 onwards on or before 31st July,2025 by writing to the Company's Registrar NSDL Database Management Ltd. 4th Floor, Tower 3, One International Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 013 or sending email at email id shambhu.singh@jkcement.com; investor.ndmlrta@ndml.in , so that we can pay the unclaimed dividends and do not transfer the said shares. You may please ignore this communication if you have already claimed the above dividend.

After the shares have been transferred to IEPF, you may claim the said shares form IEPF authorities by filling e-form No. IEPF-5 as prescribed under the provisions as aforesaid.

In compliance with the SEBI mandate as per email dated 17.01.2024, shareholders holding physical securities are required to update their KYC details, including bank information, to facilitate electronic payments of dividends. This directive is in line with SEBI's efforts to enhance the efficiency and security of transactions, as outlined in their circulars dated November 03,2021, December 14, 2021, March 16, 2023, November 17, 2023 and master circular dated May 7, 2024.

Shareholders are requested to submit their updated KYC forms to the Registrar and Transfer Agent (RTA), NSDL Database Management Ltd., to ensure uninterrupted processing of their electronic payments from April 1, 2024.

Investors can download the following forms & SEBI Circulars, which are also uploaded on the website of the company and on the website of NSDL Database Management Limited; https://www.ndml.in/rta.php#forms_section

For any further queries, you are requested to contact our Registrar and Transfer Agent: NSDL Database Management Ltd. Tel: 022-49142578/2636 and Email: investor.ndmlrta@ndml.in

Thanking you,
Yours faithfully,
FOR **J.K. CEMENT LIMITED**

SHAMBHU SINGH
COMPANY SECRETARY
FCS 5836

महाराष्ट्र: लाख करोड़ रु की परियोजनाएं

राज्य कैबिनेट ने 325 प्रस्तावों को दी मंजूरी, खुलेंगे निवेश और रोजगार के द्वार

सुशील मिश्र
मुंबई, 20 मई

उद्योग क्षेत्र में नीति अवधि समाप्त होने के कारण लंबित 325 प्रस्तावों को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। मंत्रिमंडल ने जिन प्रस्तावों का अनुमोदन किया, उनसे राज्य में 1,00,655.96 करोड़ रुपये के निवेश और 93,317 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई नीतियों में महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 और इसके तहत फैब परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन, महाराष्ट्र अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति 2018, रेडीमेड गारमेंट निर्माण, रत्न एवं आभूषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग घटकों के लिए फ्लैटबेड औद्योगिक परिसर नीति 2018 तथा महाराष्ट्र नई औद्योगिक नीति 2019 शामिल हैं। इन नीतियों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए नए बदलाव के साथ राज्य में नई नीतियां बनाने की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर चल रही है।

नीति अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे घटकों के प्रस्तावों के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है जो राज्य के विकास के लिए लाभकारी होंगे। चूंकि उपरोक्त नीतियों की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः यदि नई नीति लागू होने तक लंबित प्रस्तावों को संबंधित नीतियों के अनुसार अनुमोदित कर दिया जाए तो औद्योगिक इकाइयों में निवेश तथा सब्सिडी का रास्ता बन जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016 और उसके अंतर्गत फैब परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 313 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल 313 प्रस्तावों से 42,925.96 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है तथा इनसे 43,242 नौकरियां सृजित होंगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राकांपा नेता छगन भुजबल को मंत्री के तौर पर शामिल किया

महाराष्ट्र की अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति 2018 के तहत कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनसे 56,730 करोड़ रुपये का निवेश आने और 15,075 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। फ्लैटबेड औद्योगिक पार्क नीति 2018 के अंतर्गत रेडीमेड परिधान विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग घटकों के लिए दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनसे 1,000 करोड़ रुपये का निवेश मिलने तथा 35,000 नौकरियां सृजित होने की संभावना जताई गई है।

गरीबों के लिए नई आवास नीति

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक की व्यापक योजना शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि नीति का उद्देश्य 'मेरा घर - मेरा अधिकार' के तहत आम आदमी के लिए आवास मुहैया कराना है। नीति में निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से पुनर्विकास तक का व्यापक कार्यक्रम शामिल किया गया है। कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए किफायती और समावेशी आवास उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। किराये के आवास और भूमि बैंक बनाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी हितधारकों और योजनाओं को एक ही पोर्टल महा आवास पर लाया जाएगा। सरकारी भूमि का मानचित्रण किया जाएगा और उसे आवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आवास की मजबूती एक महत्त्वपूर्ण कारक होगी और इसे आधुनिक तकनीक के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2007 के बाद एक व्यापक और गतिशील सर्व-समावेशी नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति में ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासों की जरूरत पूरी करने पर विचार किया गया है।

कार खरीदने से पहले लेनी होगी पार्किंग

बीएस संवाददाता
मुंबई, 20 मई

मुंबई में घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है। अब यहां अपनी कार रखना भी आसान नहीं होगा। मुंबई और आसपास के इलाकों (एमएमआर) में यातायात और कार पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई कार खरीदने के लिए सख्त नियमों वाली नीति तैयार की है। इसके तहत लोगों को अब कार खरीदने से पहले यह बताना होगा कि उनके पास पार्किंग की व्यवस्था है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने नई नीति के बारे घोषणा करते हुए बताया कि जब तक कार खरीदार संबंधित नगर निकाय से पार्किंग स्पेस उपलब्धता का सार्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यह फैसला मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में लगातार बढ़ रही पार्किंग की समस्या को देखते हुए लिया गया है। राज्य की नई पार्किंग पॉलिसी को लेकर उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई। इस योजना के लागू होने के बाद एमएमआर में आम आदमी के लिए अपनी कार रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि हम राज्य में नए पार्किंग स्थल बनाने की योजना बना रहे हैं। विकास के नियमों का पालन होना चाहिए और फ्लैट बनाते समय बिल्डरों को पार्किंग स्पेस देना जरूरी होगा। अगर खरीदार के पास नगर निकाय से मिला पार्किंग अलॉटमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनकी गाड़ी रजिस्टर नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री ने माना कि एमएमआर में पार्किंग की बड़ी कमी है। इसे देखते हुए राज्य का शहरी विकास विभाग अब कुछ तयशुदा मनोरंजन स्थलों के नीचे पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी देने पर काम कर रहा है।

सरनाईक ने पॉड टैक्सी नेटवर्क के लिए राज्य की योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा कि कहा कि हम इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पर एक डिजाइन मेरे सामने रखा गया था। मैंने वडोदरा का दौरा किया है, जो दुनिया की पहली पॉड-कार परियोजना चालू करेगा। महाराष्ट्र सरकार मीरा-भयंदर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में भी इसी तरह का सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद मेट्रो नेटवर्क से संपर्क बढ़ाना है।

एएससीआई ने ओपिनियन ट्रेडिंग पर जताई चिंता

रोशनी शेखर
मुंबई, 20 मई

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने एक श्वेत पत्र जारी कर ओपिनियन ट्रेडिंग या प्रेडिक्शन मार्केट और उनसे जुड़े जोखिमों का जिक्र किया है। मंगलवार को जारी इस श्वेत पत्र में ओपिनियन ट्रेडिंग को लेकर नियामकीय स्पष्टता की जरूरत का भी जरूरत बताई गई है।

ओपिनियन ट्रेडिंग ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के नतीजों का पूर्वानुमान लगाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वास्तविक दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों जैसे समसामयिकी, फुटबॉल, शेयर, बास्केटबॉल, मोटरस्पोर्ट्स, टेनिस, मौसम आदि घटनाओं को लेकर उपयोगकर्ता (यूजर) अपने अनुमान व्यक्त करते हैं। एएससीआई ने 'एग्जामनिंग ऑपिनियन ट्रेडिंग इन इंडिया' शीर्षक नाम से प्रकाशित श्वेत पत्र में ये बातें कहीं। एएससीआई ने कहा कि कुछ देशों में इसे वित्तीय योजनाएं मानकर इनके लिए कायदे-कानून बनाए गए हैं और कुछ दूसरे देशों में जुआ अधिनियम के अंदर इनके लिए कानून बनाए गए हैं।

भारत में अप्रैल 2025 के शुरू में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगों को आगाह किया था कि ओपनियम ट्रेडिंग उसके नियामकीय दायरे में नहीं आता है।

एएससीआई यह जानने और इस पर कानूनी स्थिति को समझना चाह रहा है कि ओपिनियन ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां और उनके विज्ञापनों की अनुमति है या नहीं। एएससीआई के अनुसार उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखने के लिए कुछ विज्ञापन दिशानिर्देशों की जरूरत महसूस की जा रही है। एएससीआई ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि अगर ऐसी गतिविधियों की कानूनी रूप से इजाजत नहीं है तो सभी संबंधित पक्षों को इस मामले में नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक ढांचा स्थापित करना चाहिए।

एएससीआई की मुख्य कार्याधिकारी एवं महासचिव मनीषा कपूर ने कहा, 'ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गंभीर चिंता का कारण बन रहे हैं क्योंकि कुछ मामलों में उनके तौर-तरीके बाजी लगाने वाले खेल (जुआ) से मिलते-जुलते हैं। इससे उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय जोखिम काफी बढ़ सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म से जुड़े विज्ञापनों में आसानी से जीत दर्ज करने के दावे किए जाते हैं और इन्हें विश्वसनीय भी बताया जाता है। मगर कोई अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) नहीं दिया जाता है।' कपूर ने कहा कि एएससीआई के श्वेत पत्र में इन जोखिमों का जिक्र किया गया है और तत्काल नियामकीय कदम उठाने की मांग की गई है ताकि ओपिनियन ट्रेडिंग के जोखिमों से उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखे जा सकें।

नैशनल इनिशिएटिव फॉर कंज्यूमर इंटरेस्ट (एनआईसीआई) के अनुसार इन प्लेटफॉर्म के 5 करोड़ से अधिक यूजर हैं और सालाना 50,000 से अधिक कारोबार होता है।

श्वेत पत्र में कहा गया है कि एएससीआई की नजर में ऐसे कई विज्ञापन नजर में आए हैं जिनमें विभिन्न देसी-विदेशी खिलाड़ी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओपिनियन ट्रेडिंग को ज्ञान एवं कौशल आधारित खेल बताकर इनका प्रचार करते हैं। एएससीआई के अनुसार इन विज्ञापनों का विश्लेषण करने से पता चला है कि उनमें कुछ विशुद्ध रूप से अटकल आधारित खेल लगते हैं।

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नियम-कायदे स्पष्ट करने पर दिया जोर

6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कमी ...

पृष्ठ 1 का शेष

एक दूरसंचार कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'जियो का तरीका वैश्विक स्तर की कई दूरसंचार कंपनियों के अनुरूप है। कई देशों ने 6गीगाहर्ट्ज का अधिकांश या पूरा हिस्सा वाईफाई 6ई और वाईफाई 7 जैसे बिना लाइसेंस वाले उपयोग के लिए आरक्षित रखा है इसलिए परिचालकों ने 5जी नेटवर्क के लिए मिड बैंड स्पेक्ट्रम (3.3-3.8 गीगाहर्ट्ज) या सी-बैंड पर ध्यान केंद्रित किया है।'

दिसंबर 2023 में इंटरनैशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) ने लाइसेंस वाले मोबाइल परिचालन के लिए 6.425-7.125 गीगाहर्ट्ज को अलग किया था। यह फैसला हर तीन-चार साल में होने वाले 10वें वर्ल्ड रेडियोकम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस में लिया गया था जिसमें रेडियो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा और संशोधन किया जाता है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पहले ही पूरे 6गीगाहर्ट्ज बैंड (5925-7125 मेगाहर्ट्ज) को बिना लाइसेंस वाले इस्तेमाल के लिए आवंटित किया है। पूरे बैंड को वाईफाई इस्तेमाल के लिए खोलने के बाद ब्राजील ने बाद में नीतियों में बदलाव किया है ताकि बैंड के ऊपरी स्तर का इस्तेमाल मोबाइल फोन के लिए हो। ब्रिटेन में बैंड के ऊपरी स्तर के इस्तेमाल के लिए फैसला लेने पर विचार-विमर्श जारी है।

एसयूवी बन रही लोगों की पहली कार

पृष्ठ 1 का शेष

टीमलीज एडटेक के संस्थापक एवं सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि पिछले 5 से 7 साल में फ्रेशरों के वेतन में खास वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सालाना वेतन वृद्धि 5 से 7 फीसदी के दायरे में रही है, जो महंगाई को ही नहीं समेट पा रही है। उन्होंने कहा, 'कुछ प्रमुख शहरों में ही ज्यादा नौकरियां हैं और घर से दूर रहने पर खर्च करने लायक आय और भी कम हो जाती है। एआई के इस्तेमाल ने रोजगार बाजार को अस्थिर और अनिश्चित बना दिया है। ऐसे में लोग कार जैसी बड़ी खरीदारी करने के बजाय बचत को प्राथमिकता देते हैं।'

भार्गव ने कहा, 'कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए छोटी कारों की कीमतें कम करनी होगी। इसके लिए कर में कटौती के अलावा नियमों से होने वाला खर्च भी कम करना होगा।' अगर जीडीपी वृद्धि और यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि के बीच संबंध को देखा जाए तो वित्त वर्ष 2000 और वित्त वर्ष 2010 के बीच जीडीपी में 6.3 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि रही और यात्री वाहनों की विक्री 10.3 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ी। अगले दशक यानी वित्त वर्ष 2020 तक जीडीपी में सालाना 6.6 फीसदी

चक्रवृद्धि दिखी मगर यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि 3.6 फीसदी है। वित्त वर्ष 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री में 2 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई जबकि जीडीपी में 6.5 फीसदी इजाफा हुआ। मारुति सुजूकी के कार्यकारी अधिकारी (कॉरपोरेट मामले) राहुल भारती ने एक अन्य दिलचस्प रुझान की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, 'अभी सड़क पर 27 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। मान लें कि पिछले 5-7 सालों में 10 करोड़ दोपहिया वाहन बेचे गए हैं, तो कम से कम 17 करोड़ दोपहिया वाहन ऐसे हैं जो इससे पुराने हैं और मालिक उन्हें अपग्रेड करने पर विचार कर सकते हैं। मगर वे बाजार में नहीं दिख रहे हैं। दोपहिया वाहन को अपग्रेड करने वाले हमेशा छोटी कार खरीदते हैं।' इसलिए ऐसा लगता है कि मध्यवर्ग में दोपहिया वाहन बढ़ गए हैं।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा जैसी कंपनियों का ध्यान केवल एसयूवी पर है। उसकी सबसे कम कीमत वाली एसयूवी एक्सयूवी3एक्सओ को एक तिहाई ग्राहक ऐसे मिले हैं, जो पहली बार कार खरीद रहे हैं। कंपनी के सीईओ (ऑटोमोटिव) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि तमाम सुविधाओं से भरपूर, सुरक्षा और आराम के कारण यह नए खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प है। ह्युंडै के एक अधिकारी ने भी कहा कि भारत में बिकनी वाली हर तीन ह्युंडै कार में दो एसयूवी हैं। उन्होंने बढ़ते अरमानों और आसान कर्ज को इसका मुख्य कारण बताया। उद्योग के एक विशेषज्ञ ने इशारा किया कि प्रवेश स्तर की कार खरीदने वालों की औसत मासिक आय 65,000 से 75,000 रुपये होती है, जबकि एसयूवी खरीदने वाले की औसत मासिक आय 75,000 से 90,000 रुपये के बीच है। ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अगले तीन वर्षों के दौरान भारत में संपन्न वर्ग की तादाद लगभग दोगुनी होकर 10 करोड़ होने का अनुमान है। मगर यहां केवल 3 करोड़ लोगों की आय ही वाहन खरीदने लायक है।

उच्च आय वाले भारतीय बड़े वाहन ही पसंद नहीं करते बल्कि उनमें अधिक प्रीमियम सुविधाएं भी चाहते हैं।

JKCement

जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 | फैक्स: +91 512 2332665
ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश वर्तमान में कंपनी के पास हैं, और इन्हें सितम्बर 2025, के प्रथम सप्ताह में आई ई पी एफ को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के उन इक्विटी शेयरों को, जिनके लाभांश का दावा या भुगतान लगातार सात वर्षों या अधिक समय से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अनिवार्य रूप से अंतरित किया जाना अपेक्षित होगा, इससे सबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर "Information about IEPF" सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एतत सबंधित सूचना, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, उनके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया गया है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने दावे लिखित रूप में कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेण्ट NSDL Database Management Limited (NDML), 4th Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 013 को दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक भेज दें।

यदि कंपनी को दिनांक 31.07.2025 तक कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी सितम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित करने की दिशा में आगे की कार्यवाही करेगी। एक बार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित कर देने के पश्चात, सम्बधित सदस्य ऐसे शेयरों पर दावा केवल आई ई पी एफ प्राधिकरण को ही इस हेतु नियत प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार आई ई पी एफ को शेयर अंतरित करने के पश्चात् ऐसे दावा रहित या भुगतान रहित शेयरों की वापसी के सम्बंध में कोई भी दावा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांशों को कंपनी द्वारा पहले ही आई ई पी एफ में अंतरित किया जा चुका है। इस हेतु किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण हेतु कृपया shambhu.singh@jkcement.com / sunilk@ndml.in पर ई-मेल भेज कर अथवा टेलीफोन नं. +022 4914 2578/ 2589 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह सूचना आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा धनवापसी) नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित की गयी है।

स्थानः कानपुर
दिनांकः 20.05.2025

कृते जे. के. सीमेंट लिमिटेड
शम्भू सिंह
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं0 एफसीएस 5836

Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before 1 pm on Friday, May 30, 2025.
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	Before 09:30 pm on Friday, Thursday, May 29. All SCSBs for Direct ASBA - Before 07:30 pm on Thursday, May 29, 2025 Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on Thursday, May 29, 2025
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on Friday, May 30, 2025.
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on Friday, May 30, 2025.
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA - To all SCSBs For UPI ASBA - To Sponsor Bank	Initiation not later than 09:30 am on Monday, June 2, 2025; Completion before 2 pm on Monday, June 2, 2025 for fund transfer; Completion before 4 pm on Monday, June 2, 2025 for unblocking.
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before 2 pm on Monday, June 2, 2025 Completion before 6 pm on Monday, June 2, 2025
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on Monday, June 2, 2025
Publish allotment advertisement	On website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before 9 pm on Monday, June 2, 2025. In newspapers - On Tuesday, June 3, 2025 day but not later than Thursday, June 5, 2025.
Trading starts T+3 day	Trading starts Tuesday, June 3, 2025

** PSPs/TPAPs=Payment Service Providers/Third party application providers.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"Our History and Certain Corporate Matters"* on page 240 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 426 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- (Rupees Twenty-Five Crores Only) divided into 2,50,00,000 (Two Crore and Fifty Lakhs Only) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue Rs. 18,17,35,000/- (Rs. Eighteen Crores Seventeen Lakhs and Thirty-Five Thousand Only) divided into 1,81,73,500 (One Crore Eighty-One Lakhs Seventy-Three Thousand and Five Hundred Only) Equity Shares of face value Rs.10 each. For details of the Capital Structure, see *"Capital Structure"* on the page 82 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Mr. Sudhir Kumar Bansal-100 equity shares and Mr. Ashok Kumar Bansal- 100 equity shares, aggregating to 200 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see *"Our History and Certain Corporate Matters"* on page 240 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see *"Our History and Certain Corporate Matters"* on page 240 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 351 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 29 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled Eight (8) Public Issues in the past three years out of which Zero (0) issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of BRLM	Total Issue in last 3 years		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Fast Track Finsec Private Limited	0	8	0

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Fasttrack Finsec Category-I Merchant Banker	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence	**Ms. Shefali Gupta** **Address**: Address: A-10 Floor 1st Land Mark Near Deepali Chowk Saraswati Vihar, Pitampura, North West, New Delhi, India - 110034 **Tel.:** +91-7300712189 **E-mail:** info@nikitapapers.com **Website:** www.nikitapapers.com
FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED **Address:** Office No. V-116, 1st Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 **Tel:** +91 11 43029809; **Email:** mb@fttfinsec.com **Contact Person:** Mr. Rakesh Pathak **Website:** www.fttfinsec.com **SEBI registration number:** INM000012500 **CIN:** U65191DL2010PTC200381	**SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 **Telephone:** +91- 11-40450193-97 **Email:** ipo@skylinerta.com **Website**: www.skylinerta.com **Contact Person:** Mr. Anuj Rana **SEBI Registration Number:** INR000003241 **CIN:** U74899DL1995PTC071324	*Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.*

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of company at www.nikitapapers.com, the website of the Book Running Lead Manager to the Issue at https://www.fttfinsec.com/resource/Offer_Documents/Offer_Documents.aspx, and websites of stock exchange at www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and NSE at www.nikitapapers.com, https://www.fttfinsec.com/resource/Offer_Documents/Offer_Documents.aspx and www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATI ON FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Nikita Papers Limited (Telephone: +91 7300712189) **Lead Manager**: Fast Track Finsec Private Limited (Telephone: +91-11-43029809;). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE (www.nseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

SYNDICATE MEMBER: N.A.

BANKER TO THE OFFER/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

SPONSOR BANKS: ICICI Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For & On Behalf of the Board of Directors
NIKITA PAPERS LIMITED
Sd/-
Shefali Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: May 20, 2025

Disclaimer: - Nikita Papers Limited proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated May 20, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at https://www.fttfinsec.com/resource/Offer_Documents/Offer_Documents.aspx. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***" Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **22.02.2025** calling upon the Borrower(s) **MOHIT KUMAR AGARWAL PROPRIETOR A.M. ADHESIVES and PREETI GOYAL PROPRIETOR DD SALES** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 31,30,080.63 (Rupees Thirty One Lakhs Thirty Thousand Eighty And Paise Sixty Three Only)** against Loan Account No. **HHLDMT00484134** as on **19.02.2025** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **17.05.2025**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**) for an amount of **Rs. 31,30,080.63 (Rupees Thirty One Lakhs Thirty Thousand Eighty And Paise Sixty Three Only)** as on **19.02.2025** and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. 0602, HAVING AREA OF 165.82 SQ. MTRS., I.E 1785 SQ. FT., IN TOWER NO. V3, FLOOR NO. 6, IN THE KINGSBURY APARTMENT, TDI CITY, KUNDLI, SONEPAT-131001, HARYANA. ALONGWITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE, IN THE LAND ONLY UNDERNEATH THE SAID BUILDING OF THE APARTMENT.

Sd/-
Date : 17.05.2025 — Authorised Officer
Place : SONEPAT — SAMMAAN CAPITAL LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank
...the name you can BANK upon!

SASTRA DIVISION, 3rd FLOOR, EAST WING, PLOT NO. 4, SEC. 10, DWARKA NEW DELHI-110075
(email- horecovery@pnb.co.in/hosastrawilful@pnb.co.in)

SHOW CAUSE NOTICE

22.04.2025

1. **M/s Hind Agro Industries Ltd.**
   Regd. Office: A-1, Phase-1, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020.
   Also at: CDF Complex, Anupshehar Road, Aligarh, UP-202122.
2. **Sh. Kiran Qureshi (Director)**, 69 Siddhartha Enclave, New Delhi-110014.
3. **Sh. Sirajuddin Qureshi (Managing Director)**, 69 Siddhartha Enclave, New Delhi-110014.
4. **Sh. Samar Qureshi (Managing Director)**, 69 Siddhartha Enclave, New Delhi-110014.

Dear Sir/Madam,

Reg.: Show Cause Notice to Borrower M/s Hind Agro Industries Ltd. and its related parties (ZS:Delhi) for Identification of default in the loan account with the Bank, as "Wilful"

Please note that events of wilful default have been perceived in the captioned loan account and it is also observed that all the events of Wilful Default are intentional, deliberate, calculated and meeting the conditions set out in RBI Master Directions RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25,30 July 2024.

The facts of the matter were placed before the Committee for Identification of Wilful Defaulters ('Identification Committee-I') constituted in consonance with the RBI guidelines. The Committee, in its meeting held on 03.04.2025, after going through facts of the matter & evidence on record, has concluded that events of default has/have occurred in the account which is/are wilful and substantial to classify borrower and its related parties as 'Wilful Defaulters', inter alia for the following reasons:

Diversion of Funds:

Forensic Auditor M/s Prakash Ved & Co. (CA Firm) in his report mentioned as under

a. The money availed by the borrower company for pre-shipment was to be utilized for manufacturing the end product for export and foreign exchange had to be received towards the price of the goods exported. Huge amount which was to be received as proceeds of the export was never received and the borrower did not take any effective measures to recover the export proceeds from the foreign buyers. The foreign exchange which was to be received in the country for the products exported was never received and was diverted to foreign countries.

b. The forensic auditor observed that during the year 2015-16, the company had given long term and short-term advance payments to the tune of Rs. 154.58 Crore to most of its related parties during the same trade of business under backward and forward integration, when the market does not warrant huge advances in such types of business activities thus siphoning off major portion of business income.

c. The company has further diverted the funds by making payment as security rent to the extent of Rs.1.2 Crore to AL-Mashriq Exports, Rs. 1.8 Crore to Islamuddin & co. and Rs.0.7 Crore to Hind Biopharmaceutical Ltd. The rent agreed to be paid is also exorbitant e.g. Rs. 10 lac monthly rent to AL-Mashriq Exports, Rs.4.58 Lac monthly rent to M/s Islamuddin & Co (all their own group companies). It is important to note that when the lease deeds were required to be produced, the company did not submit the same for verification. The transactions are clearly fake transactions.

d. Misuse of Concessions of export credit facilities: The borrower company had availed the packing credit facility for making 100% export. But the company utilized export credit facility (which is available at concessional rate) in order to fund the domestic sales. During the FY ending 31.03.2015, the borrower company made purchases to the extent of Rs.482.87 Crore from M/s AL Sana Agro Foods Pvt Ltd and sold to M/s AL Hamd Agro food products Ltd to the extent of Rs.404.87 Crore and the entries for sale and purchase were squared up on the same day. Such sales and purchases were executed through Axis Bank. This indicates that these transactions were mere entries only without any underlying business activities and were meant to divert the funds only. The forensic auditor has also located an entry of Rs.2 Crore in the account of Sh. Sirajuddin Qureshi (Director), from M/s Al Hamd Agro Foods Pvt. Ltd, who is debtor in the books of the Company, indicating diversion of funds

e. Manipulated sales turnover: The borrower manipulated the sales turn over years to keep it at a consistently higher level with an intention to obtain the sanctioned credit facilities more than what it was eligible and it was misrepresentation or manipulation of facts by the borrower before the consortium of banks.

f. Export sales to single party: The company has made major exports to single party i.e. M/s Farm Land Foods Product LLP and its allied concern Al Fauq General Taj Trading LLC. The total amount receivable from the said company as on 31.03.2016 was Rs.74.88 Crore and the borrower company has suspiciously written off the whole amount without making any effort to recover the same, thus depriving the country of the foreign exchange. This amounts to diversion of funds by the borrower.

g. Suspicious write off of unrealized export bills- From January, 2015 onwards, the borrower made exports worth Rs.16.34 Crore to M/s Farm land Foods Product LLC and Rs.11.34 Crore to M/s Taj AL Fauz Trading LLC but did not realize the proceeds of the exports and instead wrote off the receivables by creating provision of Rs.78.10 Crore for bad debt in their books as on 31.03.2016. This raises suspicion that either the borrower company had received payment in advance against these bills in the name of group companies/individuals/ directors or the funds have been diverted by opening account in foreign countries or false sale were shown in books of accounts, which amounts to cheating and diversion of funds by the party.

h. Current account with other banks: The Borrower company was maintaining current account no. 913020025975391 with Axis Bank, Current A/c no. 34324773958 with SBI and Current account no. 605920110000113 with bank of India and Current account no 038701010001397 with J&K bank, contrary to the terms and conditions of the sanction. An amount of Rs.91.77 Crore was received in these accounts during the year ending March, 2016 but the said amount was not transferred to the banks of the consortium. Thus, the company diverted the funds for other purposes instead of repaying to the lenders. The borrower did not close these accounts despite several instructions from the lending banks.

i. Advance payments made but not realized- The borrower was in practice of purchasing its major portion of raw materials from one of its allied concerns, M/s Integrated Livestock Village Farm Pvt. Ltd with common directors. The borrower company had opened a current account with Axis Bank, Okhla industrial Area, New Delhi where most of the payments were received for local sales as well as advance payments from foreign buyers. Out of this, the borrower company made advance payment of Rs.55 Crore during FY 2014-15 to M/s Integrated Livestock Village farm Pvt ltd and adjusted Rs.42.41 Crore with advances of miscellaneous individual suppliers after giving credit to the account of the said company. These are not the genuine entries as there is doubt about these parties as KYC of such individual were not provided an payment to such individuals was made in round figures. The company is not making any recovery even of the present balance amounting to Rs.17.21 Crore recoverable from M/s Integrated Livestock Village Farm Pvt. Ltd

j. The statutory auditors of the company in their audit report as on 31.03.2016 stated that the company has given advances to its alleged suppliers to the extent of Rs.72.56 Crore but neither the goods were procured not the advances were called back. This gives rise to the suspicion of diversion/misuse of funds.

k. Over-valuation of stock-During the joint visit by the consortium member on 17.05.2017, it was observed that unit was not functioning and no stock was available. Despite consistency in sales turnover in last 5 years company suddenly reduced the valuation of stock by Rs.91.33 Crore in FY 2015-16 , Which indicates that company had managed/manipulated their financial statements by fraudulently inflating value of the stock in order to maintain their eligibility to continue to avail the sanctioned credit facilities or sold it and diverted the funds which amounts to cheating and misrepresentation of facts before consortium availing credit facilities more than its capacity.

Thus, the borrower firm, during 2012-2015 misrepresented or concealed the facts, submitted false information/documents and induced the bank to sanction and disburse Cash Credit and letter of Credit facilities to the tune of Rs.357.61 Crore, thereafter diverted the funds and did not repay the loan to banks and thereby caused wrongful loss of Rs.221.72 Crore to the said consortium of banks.

Supporting Documents: Forensic auditor M/s Prakash Ved & Co. (CA Firm) report dated 07.08.2017

In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the Identification Committee, you may make a submission/representation, if you so desire, to the Identification Committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as "Wilful Defaulter". Your submission/representation must reach us within 21 days of the receipt hereof and be sent either to General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Punjab National Bank, Head Office, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 or through the **Zonal SASTRA, Delhi.**

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of the Identification Committee. Please take note that pursuant to submission/ non-submission of your representation, the Identification Committee shall take appropriate action in terms of the RBI Master Directions on wilful defaulter.

Identification Committee-I constituted in consonance with the RBI directives comprises of the following members:

i. Executive Director (Head of Committee)
ii. Chief General Manager, SASTRA Division, Head Office
iii. Chief General Manager, TMD Head Office and
iv. Assistant General Manager, Law Division Head Office (Invitee)

The Identification Committee-I has authorized the undersigned to send this Show Cause Notice under his Signature.

KRISHNA PRATAP SINHA
Deputy General Manager

पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank
...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

HEAD OFFICE: PLOT NO. 4, SECTOR-10, DWARKA NEW DELHI-110075

Date: 03.04.2025

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED AT HEAD OFFICE ON 15.03.2025
M/s Amrapali Silicon City (P) Limited (Rs. 59.50 crore)
Circle SASTRA / Zonal SASTRA: New Delhi / New Delhi
Date of NPA: 30.06.2016

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID BC.22/20.16.003/2015-16 dated July 01, 2015, Committee for Identification of Wilful Defaulters issued Show Cause Notice dated 15.11.2021 to following persons mentioning the grounds on the basis of which they are identified as wilful Defaulter: -

1. **M/s Amrapali Silicon City (P) Limited (Borrower)**
2. **Sh. Anil Kumar Sharma (Director/Guarantor)**
3. **Sh. Shiv Priya (Director/Guarantor)**
4. **Sh. Pramod Kumar Aggarwal (Director)**

Vide Show Cause Notice, the above-named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they should not be classified as wilful defaulter. Representation dated **05.12.2021, and 30.11.2021,** were received against Show Cause Notice, **from Sh. Anil Kumar Sharma through Advocate Manoj Singh & Associates and Sh. Pramod Kumar Aggarwal respectively.**

Based on the representations received, the Identification Committee decided to grant the borrower and its related persons an opportunity for a personal hearing, scheduled for 23.06.2022. Representations dated 25.05.2022, and 27.06.2022, were submitted by Sh. Pramod Kumar Aggarwal and Sh. Shiv Priya, respectively, against the personal hearing notice. Sh. Pramod Kumar Aggarwal attended the hearing on 23.06.2022, and made his submissions; however, the Committee found them unsatisfactory.

During the hearing, the Committee noted that directors Sh. Anil Kumar Sharma and Sh. Shiv Priya were incarcerated and unable to attend, which was deemed contrary to the principles of natural justice. Consequently, the Identification Committee decided to place the wilfull default proceedings in abeyance in light of the directors' inability to participate in the personal hearing.

As per the RBI's new Master Directions issued on July 30, 2024, the Review Committee for wilful defaulters will provide an opportunity for a personal hearing. Hence, Identification Committee in its meeting held on 08.01.2025 after considering the case and material held on record, representation, identified the borrower and its related parties as wilful defaulters and issued Order dated 14.01.2025 vide which, the identified persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of Order, as to why they should not be classified as wilful defaulter on the following grounds:-

Capacity To pay

As per the CA certificate dated 26.05.2015, the directors/guarantors possess sufficient net means to repay the bank's dues. However, despite having the financial capacity, they are not fulfilling their repayment obligations to the bank.

Name	Net Means	CA Certificate date
Sh. Anil Kumar Sharma	Rs.740.39 Crore	26.05.2015
Sh. Shiv Priya	Rs.373.48 Crore	26.05.2015

Diversion of Funds

Hon'ble Supreme Court in the course of hearing has pointed out diversion of funds of more than Rs.2765 crores by the Amrapali Group.

Forensic Audit Report which is part of Hon'ble Apex Court order summarizes: i) Non genuine purchases from suppliers ii) Bogus expenses and cash surrendered in Income Tax search iii) Double booking of expenses iv) Unsupported cash payments- wages etc v) Gold bar purchased from Yashika Diamonds vi) Foreign investment (violation of FEMA) vii) Companies created solely for purpose of routing funds and building assets viii) Misuse of funds by Directors (i.e. salary, professional fees, use of luxury cars etc.) ix) Sale of flats at lower price (undervalued transactions) x) Group investment in other projects.

Representations dated 04.02.2025 and 24.02.2025 was received against identification Order dated 14.01.2025. In accordance with the RBI Master Directions No. DoR.FIN.REC No.31/20.16.003/2024-25 dated 30.07.2024, the borrower and its related parties were granted an opportunity for a personal hearing before the Review Committee on 15.03.2025. Sh. Pramod Kumar Agarwal (Director) appeared before the committee for personal hearing. However, the remaining directors neither attended personal hearing nor any communication received from them regarding their absence. The Review Committee deliberated over the facts, representations received/ submissions during personal hearing, of the case as under:-

Deliberation of the Review Committee

Shri Pramod Kumar Agarwal (Representor), in his representation dated 04.02.2025, has claimed that he is being falsely implicated and has sought legal recourse. He referred to a complaint under Section 156(3) read with Section 190 of CrPC, 1973, which led to the lodging of a FIR on 01.09.2023. He has attended multiple hearings, the most recent being on 15.01.2025.

The Review Committee observed that the FIR and ongoing police investigation does not establish his non-involvement in the alleged fund diversion. The bank's wilful default proceedings are based on the charges of diversion of funds. As of now, Sh. Agarwal has not provided any evidence to counter the charges levelled against him by the bank.

Furthermore, the Representor denied the allegations of wilful default, stating that he never signed any loan or guarantee documents and was unaware of their existence. He has alleged that these documents were forged with the involvement of bank officials.

The Review Committee observed that his claim of forgery remains unsubstantiated. The execution of loan and guarantee documents follows a due diligence process, including verification by bank officials. Any allegations of forgery are subject to investigation by the appropriate authorities and do not impact the ongoing wilful default proceedings.

Additionally, the Representor asserted that he was not part of the company's management and, although a director, he never attended board meetings, signed minutes, or participated in company affairs. He resigned from the directorship on 05.02.2015 and has had no involvement since.

The Review Committee observed that records confirm that Sh. Agarwal held the position of Director from 05.08.2010 to 05.02.2015. His claim is without any supporting documents and that do not absolve him of his legal responsibilities as a director during that period. Directorial obligations extend beyond active participation to overall governance and accountability for the company's financial decisions. His resignation does not negate any liabilities arising from transactions undertaken during his tenure.

In light of the investigation, the Representor requested the withdrawal of the **show cause notice and the wilful default order** against him.

The Review Committee noted that request for withdrawal of the show cause notice cannot be entertained in the absence of any evidence to refute the charges. The wilful default identification process will proceed in accordance with the bank's policies. However, as per RBI's revised Master Directions dated 30.07.2024, he has been granted an opportunity for a personal hearing on 15.03.2025 before the Review Committee.

Shri Shiv Priya (Representor) has made a representation dated 24.02.2025 against the bank's order dated 14.01.2025, which identified him as a wilful defaulter. He claimed that the bank did not verify the facts properly and issued the order under preconceived notions. He argued that the bank should not have used the Forensic Audit Report from W.P. (C) No. 940/2017, as per the engagement letter dated 10.10.2018.

The Review Committee maintained the bank's stand that the order was issued after thorough verification of facts and evidence. The use of the Forensic Audit Report was justified as it was part of the Supreme Court-mandated investigation in W.P. (C) No. 940/2017. The bank denied any preconceived notions and asserted that the order was based on credible findings. The bank clarified that the Forensic Audit Report was not used against the directions of the Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No. 940/2017. The report highlighted instances of fund diversion, non-genuine purchases, bogus expenses, and other fraudulent activities, which justify the classification of the account as a wilful defaulter.

The Representor also claimed a lack of access to documents due to custody since 11.10.2018, making it difficult to provide a detailed representation. He pointed out that the writ petition is still pending, and the Forensic Audit Report has not attained finality, making the bank's order premature. He asserted that the bank was misled by the initial Forensic Audit Report, which should not have been used as per the mandate, and the matter is still under investigation.

The Review Committee noted that Shri Shiv Priya acknowledged that documents were submitted to the Forensic Auditor but emphasized that the findings of the Forensic Audit Report, which highlight fund diversion and fraudulent activities, remain uncontested.

It was further noted that while Sh. Shiv Priya claimed a lack of access to documents due to custody, the Forensic Audit Report and other evidence used in the wilful default proceedings were obtained by the bank through lawful means and not against the Supreme Court directives. The bank asserted that the pendency of the writ petition does not preclude the bank from taking action based on the findings of the Forensic Audit Report. The report has been duly considered, and the order was issued after careful evaluation of all evidence.

Further, it was denied that the borrower was misled by the Forensic Audit Report. The report was prepared as per the Supreme Court's mandate and highlights clear instances of fund diversion and fraudulent activities, which justify the wilful default classification.

The Representor further stated that his group company has fully discharged liabilities in several projects, including Amrapali Zodiac, Amrapali Saphire, Amrapali Grand, Amrapali Eden Park, Amrapali Green, and Amrapali Village Phase I and II. He mentioned that the group has taken loans of approximately ₹2800 Cr. and repaid around ₹2300 Cr., including principal and interest, indicating no ill-will.

The Review Committee noted that while Shri Shiv Priya claims full discharge of liabilities in certain projects, these claims do not negate the fact that other accounts were classified as NPA due to non-payment of dues. It is emphasized that the borrower failed to regularize the account despite repeated intimations and follow-ups.

The Representor denied any intention to default, stating that the company repaid interest and quarterly installments until FY 2016-2017, but cash flow was impacted due to uncontrollable reasons. He confirmed that all required documents were submitted to the Forensic Auditor appointed by the Supreme Court in W.P. (C) No. 940/2017.

The Review Committee noted the assertion that failure to discharge obligations was not intentional does not diminish the fact that the borrower has failed to meet its financial obligations, which were due in accordance with the terms of the loan agreement. Therefore, the bank is within its rights to proceed with the "Wilful Default" proceedings as per the provisions of the applicable laws and regulations

Based on the facts and evidence, the bank found the explanations provided in the representation unsatisfactory and insufficient to refute the allegations of wilful default.

The Representor highlighted that the DRT and the Hon'ble Supreme Court have deemed Amrapali Group's projects economically viable, and based on this economic viability, the banks have financed their projects and disbursed loans.

The Review Committee noted that the borrower and directors primarily outlined their submissions and the orders passed by the Hon'ble Supreme Court & DRT but failed to rebut the points of wilful default mentioned in the SCN dated 15.11.2021.

The Representor stated that Supreme Court authorized the DRT Delhi to auction Amrapali Group's assets, which were valued as economically viable by the Ld. Receiver.

The Review Committee noted that while the Supreme Court authorized the auction of Amrapali Group's assets, this does not absolve the borrower of the wilful default allegations. The Forensic Audit Report and other evidence clearly indicate fund diversion and fraudulent activities.

The Representor cited the RBI Circular dated 01.07.2014 and the Supreme Court's judgement in SBI v. Jah Developers (P) Ltd, arguing that no prior hearing was provided, violating natural justice. He requested a personal hearing, stating that denial would violate natural justice and that the order was based on a Forensic Audit Report that should not have been used.

The Review Committee noted that as per the RBI's new Master Directions, the Review Committee has provided an opportunity for a personal hearing on 15.03.2025 to borrower and its related parties before the Review Committee.

Shri Pramod Kumar Agarwal appeared before the Review Committee for personal hearing on 15.03.2025 and informed that he has never signed any documents and his signatures were forged against which case is going on at CBI.

Upon being asked by the Review Committee about his role in the company, Shri Pramod Kumar Agarwal stated that he is not a promoter in the company and was only appointed on the Board. However, he never attended any meeting or took any decision.

The Review Committee duly noted the above fact.

The Review Committee noted that all earlier letters/ representations of the borrower and its related parties have been considered by the Bank. It was observed that borrower and its related parties failed to provide any concrete evidence to disapprove allegations of wilful default.

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS.

The Review Committee chaired by the MD & CEO of the Bank and the Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record, in its meeting held on 15.03.2025, concurred with the order of the Identification Committee and found that the captioned borrower and its related parties are responsible for the above events of wilful default, which constitute cogent ground of being declared as 'Wilful Defaulter' in terms of extant Bank guidelines issued in consonance with the RBI Master Directions No. **DoR.FIN.REC No.31/20.16.003/2024-25** dated July 30,2024.

S.No	Name	Designation/Status	Charges
1	M/s Amrapali Silicon City (P) Ltd.	Borrower	Diversion of Funds
2	Shri Anil Kumar Sharma	Director/Guarantor	Diversion of Funds/ Capacity to Pay
3	Shri Shiv Priya	Director/Guarantor	Diversion of Funds
4	Shri Pramod Kumar Aggarwal	Director	Diversion of Funds

The Committee directed to issue the Order accordingly and to serve the same upon the borrower and its related persons.

Review Committee-I constituted in consonance with the RBI directives comprise of the following members:

i. Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank (Head of Committee)
ii. Share Holder Director
iii. Share Holder Director and
iv. Chief General Manager, SASTRA Division, HO (Invitee)

The Review Committee-I has authorized the undersigned to send this **ORDER OF THE COMMITTEE FOR REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS** under his signature.

KRISHNA PRATAP SINHA
Deputy General Manager

उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि.
इकाईः पिपराईच (गोरखपुर) 273152

Reg. No. : PIP/2025-26/निविदा/152 — **Date : 20.05.2025**

अल्पकालिक निविदा सूचना

इस मिल के पेराई सत्र 2025-26 के लिए निम्न की आपूर्ति/कार्य हेतु अनुभवी निर्माताओ/अधिकृत डीलर/आपूर्तिकर्ताओ तथा ठेकेदारो से दिनांक 31.05.2025 शाम 6:00 बजे तक बन्द लिफाफे के द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

1. वेल्डिंग मटेरियल 2. वैक्यूम फिल्टर स्पेयर्स 3. ट्रेस प्लेट कास्ट स्टील 4. ईटीपी डिफ्यूजर 5.एस.एस. वायर नेटिंग एवं ब्रास लाइनर, 6. हाइड्रो जेट मशीन द्वारा ट्यूब क्लीनिंग 7.रिफ्रैक्टरी मैटेरियल 8.पुराना खाली प्लास्टिक ड्रम, पुराना खाली लोहे ड्रम, पुराना काला पन्नी एवं पुराने कटे-फटे चीनी के बोरे की बिक्री हेतु

निविदा फार्म की फीस रु.590.00 (**GST** सहित), धरोहर धनराशि मिल के कोषागार मे नगद अथवा मिल के इंडियन बैंक शाखा पिपराइच के खाता संख्या 50537210018 एवं **IFSC Code: IDIB000C503** में जमा करके कार्यालय कार्य दिवस मे अथवा ई-मेल द्वारा निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा। संपर्क अधिकारी सहायक अभियंता विद्युत (प्रभारी मुख्य अभियंता) मो नं. 7860659082, क्रय प्रभारी मो नं. 6389025549, **E-Mail Id: upsscdclpipraich2018@gmail.com**

नोट : निविदा खोलने की तिथि तथा धरोहर धनराशि की जानकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधान प्रबन्धक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India
A Government of India Undertaking

GOPALPURA BRANCH; Rudra Tower, B-293, Scheme 10-B Gopalpura Bypass, Jaipur, Rajasthan-302018
Ph. 9653221061 e-mail: ubin0821063@unionbankofindia.bank

DEMAND NOTICE UNDER SEC.13 (2)

To, **Mr. Nawal Kishor Dhaka S/o Sh. Nand Kishor Dhaka;** 1st Floor, Adarsh Apartment, Plot No. D/10/107, Chitrakoot, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan PIN-302021

Dear Sir,

Notice dt. 13.05.2025 issued to you u/s 13(2) of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 by Gopalpura Branch, Jaipur, the Authorised Officer, was sent to you calling upon to repay the dues in your loan account/s with us at your last known address could not be served. Therefore, the contents of the said demand notice are being published in this newspaper.

The credit facilities/loan facilities availed by you have been classified as NPA on **28.01.2025.**

You have executed loan documents while availing the facilities and created security interest in favour of the Bank. The details the credit Fcilities and secured assets are as under:

Type of Facility	Outstanding amount as on 30.04.2025	Unapplied interest as on 30.04.2025	Penal Charges	Cost/ Charges incurred by Bank	Total dues (Including interest up to 30.04.2025)
Vehicle Loan A/c No. 210616520000064 Sanctioned limit: Rs.35.00 Lakh	Rs. 26,85,671.00	Rs.1,52,743.30	Rs. 829.00	Rs. 29.50	Rs. 28,39,272.80

Total Dues: Rs.28,39,272.80 (Twenty Eight Lakhs Thirty Nine Thousand Two Hundred Seventy Two and Eighty Paisa only)

Secured Assets:- Hypothecation of Four-Wheeler described herein below:
MG GLOSTER SAVVY 7-SEATER DIESEL 2.0 TURBO, REGISTRATION NO: RJ 14 UH 7566
CHASIS NO.:- MZ7KD6JJG5H006044, ENGINE NO.: M921A077328

Therefore, you as borrower in terms of the aforesaid notice have been called upon to pay the aforesaid sum of **Rs.28,39,272.80 (Rupees Twenty Eight Lakhs Thirty Nine Thousand Two Hundred Seventy Two and Eighty Paisa only)** together with future interest and charges thereon within 60 days from the date of this publication. That on your failure to comply therewith we, the secured creditor, shall be entitled to exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002. In terms of Section 13(13) of the Act you shall not transfer the secured assets aforesaid from the date of receipt of the notice without Bank's prior consent.

Please take note of the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Yours faithfully
AUTHORISED OFFICER
Place: Jaipur — **Name: H. N. Meena**
Designation: Chief Manager

Note: Our earlier demand notice dated 13.02.2025 is hereby withdrawn and be deemed ineffective.

Oswal Agro Mills Limited
CIN: L15319PB1979PLC012267
Corporate Office : 7th Floor, Antriksh Bhawan,
22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

Notice for loss of share certificate

Notice is hereby given that the share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost/ misplaced/ stolen and the registered holder/ the legal heirs of the registered holder thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate/ letter of confirmation of Oswal Agro Mills Limited.

Folio No.	Name of shareholder	Number of shares	Share certificate no.	Distinctive No.
681141	Mrs. Shallu Jindal	157500	Please refer the note 1 below	

Note 1: Due to the large volume of share certificates held, it has not been feasible to list the individual certificate numbers and distinctive numbers in this notice. However, complete details of the lost certificates, including certificate numbers, folio number(s), and distinctive numbers, are available with the Company/Registrar and Share Transfer Agent and can be provided upon sending a request at **cs@oswalagromills.com** or **admin@skylinerta.com.**

Members of the public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the share certificate(s) as reported lost by the above-mentioned shareholder. Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of the said share certificate should lodge such claim(s) with the Company at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained, and the Company will proceed to issue duplicate share certificate.

For Oswal Agro Mills Limited
Near Jain Colony, Vijay Inder Nagar, Daba Road, Ludhiana - 141003 (Punjab)

केनरा बैंक | Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

REGIONAL OFFICE
#C3, 2nd Floor, Sector 1, Noida, Uttar Pradesh–201301,
Tel: 0120-2524896

Ref. No. 88857730000084 — **Dated: 08.05.2025**

To the Borrower/Guarantors/Mortgagor:

Borrower (Present Address) : Mr SANJAY KUMAR DAS S/O KANU CHARAN DAS, Flat No.04113, CHAI-IV, ATS Green PARADISE, Greater Noida-201203 UTTAR PRADESH

Borrower (Property Address) : Mr SANJAY KUMAR DAS S/O KANU CHARAN DAS Flat No T-05034, TOWER-5, TYPE –B, THIRD FLOOR ATS GREEN PARADISO, Admeasuring 2150 SQ FEET, situated at PLOT-GH 03, SECTOR-CHI 4, Greater Noida, Dist-GB Nagar-201310

Borrower (Permanent Address): Mr SANJAY KUMAR DAS S/O KANU CHARAN DAS KANTALIA SARDARPARA, MAKARDAH, DOMJUR HOWRAH, WEST BENGAL-711409

Guarantor(Present Address) : Mrs SATABDI GANGOPADHYAY W/O SANJAY KUMAR DAS FLAT NO. 04113 ATS GREEN CHAI-IV, ATS Green PARADISE, Greater Noida-201203 UTTAR PRADESH

Guarantor (Permanent Address) : Mrs SATABDI GANGOPADHYAY W/O SANJAY KUMAR DAS KANTALIA SARDARPARA, MAKARDAH, DOMJUR HOWRAH, WEST BENGAL-711409

Guarantor (Property Address) : Mrs SATABDI GANGOPADHYAY W/O SANJAY KUMAR DAS, Flat No T-05034, TOWER-5, TYPE-B, THIRD FLOOR ATS GREEN PARADISO, Admeasuring 2150 SQ FEET, situated at PLOT-GH 03, SECTOR-CHI 4, Greater Noida, Dist-GB Nagar-201310

SUBJECT: Notice for exercising the right of redemption under Section 13 (8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act").

The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Noida Morna Branch, (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Act do hereby issue this notice, under Section 13(8) of the Act read with Rule 8(6) of the SARFAESI Rules, to you all as under:

As you all are aware that the secured creditor had issued the Demand Notices, under Section 13(2) of the Act, on 01.03.2025 (date of Demand Notice), to the borrower **Mr SANJAY KUMAR DAS S/O MR. KANU CHARAN DAS (hereinafter referred to as "the Borrower") and Mrs SATABDI GANGOPADHYAY W/O SANJAY KUMAR DAS** (hereinafter referred to as "the Guarantor") demanding to pay an amount of Rs. 32,23,444. (Rupees Thirty Two Lakhs Twenty three Thousand Four Hundred Forty Four only)and interest stated thereon within 60 days from the date of receipt of the said notices.

Since, the Borrowers / Firm, the mortgagors and the Guarantor (above mentioned names) having failed to repay the amount mentioned in the above said demand notices, the Authorized Officer under Section 13(4) of the Act had taken symbolic/Physical possession of the secured assets described in the Possession Notice dated 06.05.2025 . Further, the said symbolic/ Physical possession notice was duly published in BUSINESS STANDARD (Name of newspaper in local language) and BUSINESS STANDARD(Name of English Newspapers) newspapers on 08.05.2025 (Date of publication).

To comply with the provision of SARFAESI Act, 2002 read with Rule 8(6) of SARFAESI Rules, you all are hereby given a last and final opportunity to redeem and reclaim the secured assets, which are in possession of the secured creditor, within 30 days from the receipt of this notice, by discharging the liability of Rs 31,25,492/-(Rupees thirty one Lakhs twenty five Thousand four Hundred ninety two only)as on 08.05.2025, plus subsequent interest, costs and expenses in full, failing which the sale notice under the Act will be published in the newspaper specifying one of the following modes mentioned below, to sell the secured assets:

i. By obtaining quotations from the persons dealing with similar secured assets or otherwise interested in buying assets; or
ii. By inviting tenders from the public; or
iii. By holding public auction including through e-auction mode; or
iv. By private treaty.

As per Section 13(8) of the Act, you are entitled to redeem the secured Assets at any time before the date of publication of sale notice in Newspapers, failing which your Right to redeem the mortgaged property as per Section 13(8) of the Act shall stand extinguished.

This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the subject Act/ or any other law in force.

Thanking You.
CANARA BANK,
AUTHORISED OFFICER

Hinduja Housing Finance Ltd.
HINDUJA HOUSING FINANCE

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015, and Branch office: A.K Tower, 2nd Floor, 56 Subhash Road, Dehradun 248001 Email: auction@hindujahousingfinance.com

ALM - Parmod Chand, Mob No.- 9990338759 • **CLM** - Anshika Rana Mob No.- 8755056111

PUBLIC NOTICE OF PHYSICAL POSSESSION OF IMMOVABLE PROPERTY

To,
1. **Mr. AAKASH OM PRAKASH (Borrower),** Narasan Kalan, Haridwar, Uttarakhand - 247670
2. **Mrs. CHAYA (Co-borrower)**
   31 SAINIK COLONY, VALMIKI, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand - 247666
3. **Mr. AAKASH OM PRAKASH, Mrs. CHAYA (Property Address)**
   Part of Mutalika khasra no. 1407/1 mi, Padali Gujjar, pargana & tehsil-Roorkee Tehliwala, Valmiki Mandir Roorkee, Uttarakhand, 247667

LAN No. UT/UTK/DHON/A000000942 & DL/RUK/ROKE/A000000270

Whereas vide Order dated 04.02.2025 passed by District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, the physical possession of the property being All that piece and parcel of " One House Constructed on the of land, measuring in East 21 feet 2 Inch in West 21 feet 2 Inch in North 43 feet 11 Inch in South 44 feet total area 930.415 Sq. feet or 86.469 sq meter Coved area 1184.407 sq feet, pertaining to part of khasra no. 1407/1 mi situated in Village Padali Gujjar (within limit of Nagar Panchyat Padali Gujjar) Pargana and Tehsil and Distt Haridwar- 247670" has been taken over by M/s Hinduja Housing Finance Ltd. on 14.05.2025.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of M/s Hinduja Housing Finance Ltd.

Date: **21-05-2025,** Place: **Roorkee** — **Authorised Officer,** For Hinduja Housing Finance Limited

---

Indian Overseas Bank

JAISALMER BRANCH; B-447 Near Mandir Palace Parking Jaisalmer (M). JAISALMER, RAJASTHAN-345001 Mobile: 8288848555: & Email id: iob2428@iob.in)

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (for immovable property) [(Rule 8(1)]

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the **Indian Overseas Bank JAISALMER. B-447 Near Mandir Palace Parking. Jaisalmer (M), JAISALMER, RAJASTHAN 345001**, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforce- ment) Rules, 2002 issued a **demand notice dated 09/12/2024** calling upon the Borrowers/Mortgagors/Guarantors:- **Shri/M/S SHREE NAGNECHI AQUA, OPP. SHREE MAJISA TEMPLE, KACHCHI BASTI, POLICE LINE, JAISALMER, RAJASTHAN-345001, SUMER SINGH RATHORE,** (hereinafter referred as 'borrowers') to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.24,51,646.95 (Twenty-four lakh, fifty one thousand, six hundred forty six and paisa ninety five) as on 02/12/2024** with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

(1) The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **20th day of May of the year (2025)**

(2) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Indian Overseas Bank** for an amount of **Rs.24,51,646.95 (Twenty-four lakh, fifty one thousand, six hundred forty six and paisa ninety five) as on 02/12/2024** with interest thereon at contractual rates & rests as agreed, charges etc., from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession is **Rs. 26,25,853/- (Twenty-six lakh, Twenty five thousand, Eight Hundred Fifty Three only)** payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment. (3) The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY

Nature of security:- **1.Hypothecation:- Hypothecation of Machineries. 2.Mortgage:-** All that part and parcel of immovable property situated at residential Plot No-4, at Khasra Nos. 43/323, 43/367, 43/368, 43/369, 43/370, 43/371, Village-Darbari Ka Gaon, **JAISALMER,** Raj. **Admeasuring 2223.74 sq.ft.** in The Name of **Sumer Singh S/o Jethu Singh. Bounded by:- East:** Khasra No.38, **West:** Road 30 feet**, North:** Plot No.5, **South:** Road 30 feet

Date: 20.05.2025; Place: JAISALMER — **SD/- Authorized Officer, Indian Overseas Bank**

Repco Home Finance Limited
JODHPUR BRANCH: Plot No. 178, Shree Narayanam, 6th Upper Chopasni Rd, Near Bombay Motor Circle, Baldev Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342003

E - AUCTION SALE NOTICE

Sale of Immovable Properties Mortgaged to Repco Home Finance Ltd. Under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act 2002

Whereas the **Borrower: Mr.Rakesh Sharma,** S/o.Gopilal Sharma and **Co-Borrower: Mrs.Monika Sharma,** W/o.Rakesh Sharma, have borrowed money from **Repco Home Finance Limited, Jodhpur Branch** against the mortgage of the immovable property more fully described in the schedule hereunder. Since, the Borrowers failed to repay the loan amount, the company has issued a **Demand Notice** under Section 13(2) of the Sarfaesi Act, 2002 on **25.06.2024** calling upon them to repay the amount mentioned in the notice vide **Loan Account No.NHL10010275000071 being ₹3,61,657/- with further interest from 14.06.2024** together with costs and expenses within 60 days from the date of the said notice.

Whereas the Borrower, Co-Borrowers & Guarantor having failed to pay the amount due to the Company as called for in the said demand notice, the Company has taken possession of the secured asset more fully described in the schedule hereunder by issuing **Possession Notice** under Section 13(4) of the Act on **05.11.2024.**

Whereas the borrowers having failed to pay the dues in full, the secured creditor, Repco Home Finance Limited has decided to sell the under mentioned secured asset in **"As is where is condition" and "As is what is condition"** under Section 13(4) of the Act read with Rules 8 & 9 of the Security interest (Enforcement) Rules 2002 for realization of the debts dues to the company. The dues of the borrower being vide Loan Account No.**NHL10010275000071** being **₹ 4,26,057/- as on 12.05.2025.**

Date / Time of E - Auction: 26.06.2025, 11.00 a.m. - 12.00 Noon
(with unlimited auto extension of 5 minutes)

Last Date & time for submitting E-Tenders: 25.06.2025, 04.00 p.m

DESCRIPTION OF THE PROPERTY: All that piece and parcel of property bearing **No.E-11/304, [EWS], III Floor, Affordable Housing Policy Model No.4, K.No.667,668,670,671,672,673 to 677, Gram-Chokha, Jodhpur Dist–Jodhpur Raj (hereinafter referred as the said property) admeasuring area – 325** super built up area four boundaries of the said property: North: Road-40'feet, South: Flat No.E-11/301, East: Entrance, West: Flat No.E-11/303.

RESERVE PRICE ₹ **4,98,000/-** | **EMD** (10% of Reserve Price) ₹ **49,800/-** | Minimum Bid Increment Amount ₹ **10,000/-**

For E-Auction procedure, please **Contact M/s.4Closure, Mr.M.Dinesh - 81420 00735, 81420 00061.**

For inspection of the property the intending bidders may contact the Branch Head, **Repco Home Finance Limited, Jodhpur Branch,** on all working days between **10 a.m & 5 p.m. Contact Nos.89398 56934 & 0291-2950023.**

Date: 14.05.2025 — **Authorised Officer, Repco Home Finance Limited**

Manibhavnam Home Finance India Private Limited

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
APPENDIX IV Rule 8 (1)

Whereas the Authorized officer of ManiBhavnam Home Finance India Pvt. Ltd., a (hereinafter referred to as "MBHF"). MBHF, which has duly been Authorised by the Central Government, vide a notification dated 17.06.2021, to be treated as a Financial Institution, for the purposes of the "The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, having its **Registered Office At:-2nd Floor, N-2, South Extension Part-1, New Delhi-110049**, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice to the following borrowers and co-borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on as per under mentioned Date. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "MBHF" and interest other charges thereon. The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name of the Borrower /Co-Borrower :- 1. **Punam Sharma W/o Hari Shankar Sharma 2. Hari Shankar Sharma S/o Mohan Lal Sharma Add;-** 176 A, Shree Ram. Vihar, Agra Road, Jamdoli, Jaipur - 302051, Rajasthan. Also At: Hari Shankar Sharma S/o Mohan Lal Sharma Flat No. 604, 5th Floor, Aarohi Homes, Plot No. 177 178, Patel Nagar, Near Dadu Dayal Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur 302020, Rajasthan.

Demand Notice Dated :- 01.03.2025 **Date of Possession:-** 13-05-2025
Loan Agreement No. HL0000000009572
Amount of Demand Notice :- Rs. 45,42,846.35/- as on 16.02.2025

Description Of Immovable Property/Secured Asset Is As Under :- All that piece and parcel of Flat No. 604, 5th Floor, Aarohi Homes, Plot No. 177, 178, Patel Nagar, Near Dadu Dayal Nagar, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur 302020, Rajasthan. Owned By Hari Shankar Sharma

Date :- 21.05.2025 — **Authorised officer**
Place :- Jaipur — **Manibhavnam Home Finance India Private Limited**

JKCement
J.K. Cement Limited
(CIN: L17229UP1994PLC017199)
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh
Telephone : +91-512-2371478 Fax : +91-512-2332665
Email : shambhu.singh@jkcement.com Web : www.jkcement.com

Transfer of unclaimed/unpaid Dividend and Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund

Members are hereby informed that unclaimed dividend for the Financial Year ended 31st March, 2018 and the Equity Shares of the Company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed for seven consecutive years from the financial year ended 31st March, 2018 will become due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) in the first week of September, 2025, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. The relevant details are available on the Company's website www.jkcement.com under the section 'Information about IEPF'. Individual letter in this regard has been sent to the concerned Members at their address registered with the Company / the Depository Participants.

Members are advised to lodge their claims in respect of the above by writing to our RTA M/s. NSDL Database Management Limited (NDML) 4th Floor, Tower 3, One International Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 013 by 31st July, 2025. If any valid claim is not received by NDML on or before 31st July, 2025, the Company shall proceed to transfer such unclaimed dividend and shares to IEPF in accordance with the aforesaid provisions of law. Once these unclaimed dividend and underlying shares are transferred to IEPF, such shares may be claimed by the concerned Members only from IEPF Authority and no claim from the shareholders whose unclaimed dividend and underlying shares stand transferred would be entertained by the Company.

The unclaimed and unpaid dividends for the Financial Year ended and 31st March, 2017 have been transferred to IEPF and underlying share have been transferred to IEPF as informed earlier.

Clarification on this matter, if required, may be sought by sending e-mail at shambhu.singh@jkcement.com or sunilk@ndml.in or by calling at telephone No. 022-4914-2578/2589.

This Notice is published pursuant to the applicable provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

For **J.K. Cement Limited**
Shambhu Singh
Vice President & Company Secretary
ICSI Membership No. FCS 5836

Place : Kanpur
Date : 20.05.2025

सर्विलांस ने पकड़ा डॉ. अनुष्का का सात घंटे लंबा झूठ

डॉक्टर की मौजूदगी में हुआ था विनीत और मयंक का हेयर ट्रांसप्लांट, ओटी में ग्लव्स और मास्क लगाकर दे रही थी निर्देश

मौत का ट्रांसप्लांट

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बहुचर्चित हेयर ट्रांसप्लांट कांड की तफ्तीश में पुलिस को चौंकाने वाली कई जानकारियां मिली हैं। क्राइम ब्रांच की जांच से उजागर हुआ है कि मरने वाले दोनों इंजीनियर विनीत दुबे और मयंक कटियार के हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त डॉ. अनुष्का त्रिपाठी भी मौजूद थीं। दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट जिन तारीखों पर हुए उस दिन की सात घंटे तक इन दोनों के साथ ही डॉ. अनुष्का की सर्विलांस के जरिए लोकेशन भी एक साथ एक ही जगह मिली है। इससे जाहिर है कि अनुष्का ने छह बिंदुओं का जो बयान पुलिस को भेजा था वो झूठ का पुलिंदा था।

अभी तक डॉ. अनुष्का द्वारा यही दावा किया जा रहा था कि विनीत और मयंक के हेयर ट्रांसप्लांट बर्रा में किसी और सेंटर पर हुए थे जहां वह मौजूद नहीं थीं। उनका यह भी दावा था कि न तो ट्रांसप्लांट के वक्त वह मौजूद थीं और न ही उनके सेंटर पर ट्रांसप्लांट हुआ। क्राइम ब्रांच की जांच ने इस झूठ की कलई खोल दी है। तफ्तीश में क्राइम ब्रांच के पास लोकेशन हाथ लगने से मजबूत साक्ष्य भी हासिल हो गया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉ. अनुष्का खुद मास्क और ग्लव्स पहनकर मौजूद थीं और लगातार निर्देश दे रहीं थीं।

आरोपित डॉ. अनुष्का।

मयंक कटियार और विनीत की फाइल फोटो।

18 नवंबर और 13 मार्च को क्लीनिक की लोकेशन

पुलिस ने जांच में इसे प्रमुख बिंदु बनाया कि विनीत और मयंक के परिजनों के साथ अनुष्का के बयान का सच क्या है। यही वजह है कि ट्रांसप्लांट की तारीखों को जांच का सबसे खास आधार बनाया गया। परिजनों के मुताबिक 18 नवंबर को फर्रुखाबाद के मयंक का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। 19 नवंबर 2024 को मौत हुई थी। पनकी पावर प्लांट के असिस्टेंट इंजीनियर विनीत दुबे ने 13 मार्च 2025 को हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। 15 मार्च को उनकी रीजेंसी अस्पताल में मौत हो गई थी। लिहाजा पुलिस ने ट्रांसप्लांट की दोनों तारीखों पर विनीत, मयंक और डॉ. अनुष्का की मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो सच सामने आ गया। यह साफ हो गया कि इन तारीखों पर सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे यानी सात घंटे तक की एक साथ ही लोकेशन मिल गई। खास बात यह कि यह लोकेशन डॉ. अनुष्का के ही क्लीनिक की है। इससे डॉ. अनुष्का का यह दावा भी झूठा निकला कि ट्रांसप्लांट उनके क्लीनिक में नहीं हुआ।

मृतकों के परिजनों के ये बयान भी जांच में अहम

पुलिस की पूछताछ में हेयर ट्रांसप्लांट कराने वालों और मृतकों के परिजनों के बयान भी जांच में अहम हैं और लोकेशन से मेल खा रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले रामजी सचान ने बताया ग्लव्स और मास्क पहनकर डॉ. अनुष्का खड़ी रहती थीं। लड़कों को निर्देश देती थीं। मयंक कटियार की मां प्रमोदिनी ने भी ऐसा ही बयान दिया है।

मयंक के भाई ने कहा-भैया को छोड़ने बाहर आई थी

मयंक का छोटा भाई कुशाग्र हेयर ट्रांसप्लांट के समय क्लीनिक के बाहर मौजूद था। वह इस घटना का चश्मदीद भी है। उसने पुलिस को बताया है कि भैया स्वेटर पहने हुए थे। डॉक्टर अनुष्का ने कहा कि भैया का स्वेटर उतार दो। इस पर उसने टीशर्ट खरीदकर दी थी और स्वेटर उतार दिया था।

गवाह तीनों युवतियों की तलाश शुरू

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। केशवपुरम में डॉ. अनुष्का का क्लीनिक तीन युवतियां संभालती थीं। हिन्दुस्तान की पड़ताल में यह तथ्य सामने आने के बाद अब पुलिस इन तीनों युवतियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक इन युवतियां के बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि अभी पुलिस के पास इनके पते नहीं हैं। लिहाजा इनके पते की जानकारी जुटायी जा रही है।

इन युवतियों की बयान के बाद डॉ. अनुष्का के पूरे खेल का खुलासा हो जाएगा। बहरहाल पुलिस के पास इतने सबूत हैं जो डाक्टर की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। केस और मजबूत हो, इसके लिए और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। डॉ. अनुष्का के क्लीनिक में जो युवक हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। जांच में आया है कि डॉ. अनुष्का हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ही इन्हें हायर करती थी।

बिना अधिकार डाक्टर कर रही थी हेयर ट्रांसप्लांट : पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉ. के पास रोहतक मेडिकल कालेज से बीडीएस यानी दांतों के इलाज की डिग्री है। इसी डिग्री के आधार पर वह कानपुर के प्रैक्टिस कर रही है। नियम है कि दूसरे प्रदेश की डिग्री से प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उस प्रदेश के मेडिकल एसोसिएशन में भी पंजीकृत होना चाहिए लेकिन डॉ. अनुष्का ने ऐसा नहीं किया। उसने यूपी मेडिकल एसोसिएशन में पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में उसे कानपुर में इलाज का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनीत के दिल का वजन था 450 ग्राम

कानपुर। सहायक अभियंता विनीत दुबे का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का कहना है कि उसका चेहरा, होंठ और नाखून नीले पड़ चुके थे। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा जिससे उसके चेहरे पर सूजन थी। सिर पर हेयर ट्रांसप्लांट के निशान भी मिले थे। दिल का वजन 450 ग्राम था। इसे 300 ग्राम होना चाहिए था। फेफड़े का वजन 450 था जबकि इनका वजन 650 ग्राम के आसपास होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ पता नहीं चल रहा था जिसके चलते ब्लड सैंपल, लिवर, छोटी बड़ी आंत का टुकड़ा और दोनों गुर्दों से सैंपल लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

इनकी सुनिए

"अनुष्का डेंटिस्ट है, इनका कानपुर आईएमए या यूपी आईएमए से कोई सरोकार नहीं है। इनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का कोई अधिकार नहीं है। -**डॉ. नंदिनी रस्तोगी,** प्रेसिडेंट आईएमए कानपुर

"इसकी सीडीआर पुलिस के पास है। क्लीनिक में काम करने वाले सभी लोगों से पुलिस संपर्क कर रही है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। -**दिनेश कुमार त्रिपाठी,** डीसीपी पश्चिम

"विनीत का बीपी हाई था अथवा उसके वाल्व में गंभीर दिक्कत थी। हार्ट की नसें भी डैमेज हो रही थीं, दिल बढ़ा होने के यही कारण हो सकते हैं। -**डॉ. आरके वर्मा,** निदेशक कार्डियोलॉजी

"डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार ओएमएफएस से एमडीएस करने वाले डेंटिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए योग्य माने गए हैं। -**डॉ. अवधेश तिवारी,** अध्यक्ष आईडीए कानपुर

सूफी खानकाह ने तुर्किये से नाता तोड़ा

विरोध

- सूफी शाखाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े थे, अब नहीं रहेगा रिश्ता
- तुर्की के शेख उजैर की खिलाफत रद्द की, कहा वतन से मोहब्बत जरूरी

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ऑल इंडिया सूफी खानकाह एसोसिएशन ने मंगलवार को तुर्किये से नाता तोड़ लिया। कहा, भारत विरोधी किसी भी व्यक्ति और देश से एसोसिएशन कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। तुर्की के शेख उजैर की खिलाफत (नेतृत्व) को भी रद्द कर दिया। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर कार्रवाई के बाद भारत के खिलाफ खड़े हुए तुर्किए का विरोध करते हुए उसका बायकॉट शुरू कर दिया गया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खानकाह फैजिया मजीदिया के गद्दीनशीन सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने तुर्किये के शेख उजैर बिन मोहम्मद अल समसूनी को अपने स्तर से दी गई खिलाफत और इजाजत को रद्द कर दिया है।

सूफी कौसर ने कहा कि 28 जुलाई 2023 को तुर्किये के शेख को सिलसिला ए आलिया, कादरिया, चिश्तिया समेत अन्य सूफ़ी परंपरा के उन सभी सिलसिले (स्कूल क्रम), जिनकी ख़िलाफत ओ इजाज़त (नेतृत्व) का अधिकार हमें हासिल है, उनकी ख़िलाफत और इजाज़त शेख उजैर को दी थी। इसे ही निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि हम सूफियों को वतन से मोहब्बत का दर्स दिया गया है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हर उस शख़्स तंजीम या वतन जो हमारे मुल्क का जर्रा बराबर भी मुखालिफ (खिलाफ) हो उसके साथ ताल्लुक रखना देश के प्रेम के उसूलों को खंडित करता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की हिमायत में तुर्किये खड़ा हो गया, जो हमारी गैरत के खिलाफ है।

वाया गोविंदपुरी एक और ट्रेन 24 मई से

कानपुर। रेल प्रशासन ने नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के मद्देनजर एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 24 से साप्ताहिक हर शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन गोविंदपुरी होकर आएगी और जाएगी। बुधवार से इसमें रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा।

ये रहा शेड्यूल : 05219 स्पेशल ट्रेन हर शनिवार मुजफ्फरपुर से चलेगी। यह मुजफ्फरपुर से 13.30 बजे चलर गोविंदपुरी आधी रात के बाद 2.00 बजे आएगी। पांच मिनट बाद चलकर आनंदविहार सुबह 10 बजे पहुंचाएगी। यह ट्रेन 24 मई से 19 जुलाई तक चलेगी। **05220** स्पेशल ट्रेन आनंदविहार से हर रविवार आनंदविहार से चलेगी।

सजा के डर से भाग निकला डॉक्टर, गिरफ्तारी वारंट

- 14 मई से डॉ. पत्नी की हत्या के मामले में चल रहा है फरार
- पुलिस कमिश्नर को कोर्ट का पत्र, 22 तक गिरफ्तार कर पेश करें

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज के लिए डॉ. पत्नी की हत्या करने के एक मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। मंगलवार को इस मामले में फैसला आने की उम्मीद थी। आरोपी कोर्ट के बाहर मौजूद था। जैसे ही केस की पुकार हुई वह भाग खड़ा हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 22 मई तक उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

प्रयागराज के नैनी निवासी अर्जुन प्रसाद ने बेटी डॉ. मंजू वर्मा की शादी 29 जनवरी 2019 को रायबरेली चतुर्भुजपुर आईटीआई कॉलोनी, हाल पता बिठूर सिंहपुर रोड कल्याणपुर निवासी डॉ. सुशील वर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही सुशील, जेठ सुनील दत्त, देवर सुधीर कुमार समेत अन्य ससुरालीजन फ्लैट के लिए 30 लाख रुपये की मांग करने लगे। आरोप था कि मांग पूरी न होने पर आए दिन बेटी को प्रताड़ित करते थे।

14 मई की देर रात सुधीर ने मंजू के आठवीं मंजिल से चक्कर खाकर गिरने की सूचना दी। मौके पर परिवार पहुंचता तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। अर्जुन ने ससुरालीजनों के खिलाफ बिठूर थाने में दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला एडीजे-14 की कोर्ट में विचाराधीन है। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था। सुशील कोर्ट के बाहर खड़ा था। पुकार कराए जाने पर वह भाग गया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि इस मुकदमे का निस्तारण उच्चत्तम न्यायालय के आदेश पर वरीयता से किया जाना है।

अभियुक्त न्यायालय कक्ष के बाहर मौजूद था, पुकार पर कोर्ट में नहीं आया। उसकी तरफ से कोई प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया। 22 तक उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।

शोक संदेश

ॐ शांति ! ॐ शांति !!

।। जीवन को मैंने सौंप दिया है शेष तुम्हारे चरणों में ।।

हमारे पूज्य स्मृतिशेष

श्री दिनेश चन्द्र मिश्र जी

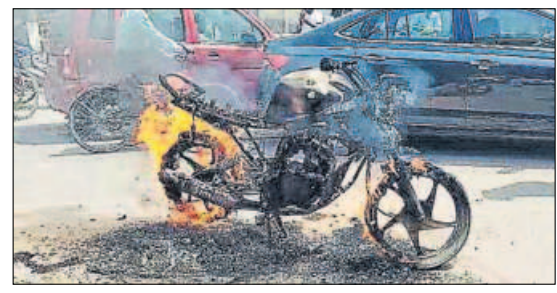

का निधन सोमवार को नई दिल्ली में हो गया था।
उनका अंतिम संस्कार 21 मई, बुधवार को कानपुर में किया जाएगा।
अंतिम यात्रा प्रात: 10 बजे हमारे निवास ''शेष सदन'',
16/60 सिविल लाइंस से भगवत दास घाट,
कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी।

शोकाकुल

श्रीमती बिमला मिश्रा
अनंत मिश्रा (अंटू) पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार - शिखा मिश्रा
अनुराग - ऋतु मिश्रा, अमिताभ-दिव्या मिश्रा, अभिषेक-नमिता मिश्रा,
अनुव्रत-प्रिया मिश्रा, सुष्मिता, अरहन,
अरनव, अनय, सुमय, अवी, अनिका,
शिवम तिवारी

कानपुर विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

''एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आनलाइन मैप संख्या–के0डी0ए0 / बी0पी0 / 2024–25 / 1262 श्रीमती सुभाषनी खन्ना द्वारा मकान नं0–16 / 19 ए सिविल लाईन कानपुर पर पेट्रोल पम्प हेतु आवेदन किया गया है। उक्त स्थल का भू–उपयोग कानपुर महायोजना–2021 में आवासीय है। कानपुर महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया सर्शत से अनुमन्य है। शर्त यह है कि भूखण्ड के सम्मुख 24.00 मी0 चौड़ा विद्यमान मार्ग होना चाहिए कानपुर महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार सर्शत से अनुमन्य किये जाने के अन्तर्गत कानपुर महायोजना–2021 में दर्शित उपयोग से इतर क्रिया / उपयोग सर्शत से अनुमन्य उपयोग में अनुमन्य किये जाने से पूर्व उ0प्र0 नगर नियोजन एवं अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। तत्क्रम में जन–सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति / संस्था को उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव देना हो तो मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के मोतीझील स्थित कार्यालय (प्रथम तल) में लिखित रूप से उक्त सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति / सुझाव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(अभय कुमार पान्डेय)
सचिव
कानपुर विकास प्राधिकरण

JKCement

जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर- 208 001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478 | फैक्स: +91 512 2332665
ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश वर्तमान में कंपनी के पास हैं, और इन्हें सितम्बर 2025, के प्रथम सप्ताह में आई ई पी एफ को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के उन इक्विटी शेयरों को, जिनके लाभांश का दावा या भुगतान लगातार सात वर्षों या अधिक समय से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अनिवार्य रूप से अंतरित किया जाना अपेक्षित होगा, इससे सबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर "Information about IEPF" सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एतत सबंधित सूचना, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, उनके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया गया है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने दावे लिखित रूप में कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेण्ट NSDL Database Management Limited (NDML), 4th Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 013 को दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक भेज दें।

यदि कंपनी को दिनांक 31.07.2025 तक कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी सितम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित करने की दिशा में आगे की कार्यवाही करेगी। एक बार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित कर देने के पश्चात, सम्बधित सदस्य ऐसे शेयरों पर दावा केवल आई ई पी एफ प्राधिकरण को ही इस हेतु नियत प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार आई ई पी एफ को शेयर अंतरित करने के पश्चात् ऐसे दावा रहित या भुगतान रहित शेयरों की वापसी के सम्बंध में कोई भी दावा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांशों को कंपनी द्वारा पहले ही आई ई पी एफ में अंतरित किया जा चुका है। इस हेतु किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण हेतु कृपया shambhu.singh@jkcement.com / sunilk@ndml.in पर ई-मेल भेज कर अथवा टेलीफोन नं. +022 4914 2578/ 2589 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह सूचना आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा धनवापसी) नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित की गयी है।

स्थानः कानपुर
दिनांकः 20.05.2025

कृते जे. के. सीमेंट लिमिटेड
शम्भू सिंह
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप सं0 एफसीएस 5836

शहर 30s

35 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन

कानपुर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को नामित ज्ञापन श्रम अधिकारी को सौंपा। 35 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनियनों ने एकजुटता दिखाई। श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने श्रम विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आगामी 9 जुलाई को देश में चक्का जाम आंदोलन छेड़ा जाएगा। मौके पर असित कुमार सिंह संयोजक, पीएस बाजपेई, राजीव खरे, राणा प्रताप सिंह, तारणि कुमार पासवान, आरडी गौतम, एचएन तिवारी, गौरव दीक्षित, मीनाक्षी सिंह, मो वशी, एसएएम ज़ैदी रहे।

लोहे के पाइप लदे ट्रक को जीएसटी से छुड़ाया

कानपुर। गुजरात से 35 टन लोहा पाइप लादकर कानपुर आ रहे ट्रक को मंगलवार सुबह फतेहपुर सीकरी में आगरा स्टेट जीएसटी के सचल दल ने रोक लिया। अफसर ई–वे बिल में पिन कोड की कमी बताकर उसे सीज करने लगे। इसकी जानकारी व्यापारी वेद प्रकाश जायसवाल ने भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के ज्ञानेश मिश्रा को दी। ज्ञानेश ने बताया कि उन्होंने सचल दल इकाई सीटीओ प्रभात सिंह से बात की और कहा कहा कि टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल में सब कुछ ठीक है। पिन कोड जैसी मामूली कमी बताकर गाड़ी सीज करना गलत है। लंबी बहस के बाद एक घंटे बाद गाड़ी छोड़ी गई।

अंकल कहने पर डिलीवरी ब्वॉय को बेल्ट से पीटा

कल्याणपुर। अंकल कहने पर भड़के एक युवक ने डिलीवरी ब्वॉय को बेल्ट से बेरहमी से पीट दिया। रोशन नगर में हुई इस घटना के बाद डरे डिलीवरी बॉय ने रावतपुर थाने में तहरीर दी। रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शास्त्री नगर निवासी दिव्यांशु गुप्ता एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है। 16 मई की रात वह डिलीवरी के लिए गया था। आरोप है कि परचून की दुकान के पास खड़े युवक को अंकल कहकर उसने पता पूछा। जिस पर भड़के युवक ने बेल्ट निकालकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

नशेबाजी के विरोध में भाइयों का सिर फोड़ा

कानपुर। कोतवाली स्थित गुप्तार घाट के पास नशेबाजी के विरोध में आरोपितों ने दो भाइयों को पीटकर सिर फोड़ दिया। शोर–शराबा सुनकर इलाकाई लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। स्वरूप नगर निवासी दीपक बागला ने बताया कि बीती 18 मई को वह अपने भाई मोहित के साथ सिविल लाइन्स में रहने वाले दोस्त के घर जा रहा था। गुप्तार घाट पर बीच चौराहे पर कार खड़ी कर चार युवक शराब पी रहे थे। उन्होंने कार हटाने के लिए बोला तो आरोपित गाली–गलौज करने लगे। विरोध पर आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी।

मेट्रो का माल चुरा रहे चोर को पकड़ा, भेजा जेल

कानपुर दक्षिण। सीटीआई के पास चल रहे मेट्रो निर्माण की सामग्री चुरा रहे शातिर को कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे गोविंदनगर पुलिस को सौंप दिया। जहां से पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। कर्रही निवासी निखिल गुप्ता ने बताया कि वह मेट्रो निर्माण से जुड़े काम देखने वाली कंपनी सीगल में एडमिन हैं। उनके अनुसार सीटीआई के पास मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है। सोमवार दोपहर पौने तीन बजे पिलर संख्या 61 के पास से स्कूटी सवार युवक ने मेट्रो निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लोहे की जाली को चोरी कर स्कूटी में रख ली।

डंपर में घुसा कंटेनर, केबिन में फंसा चालक

सचेंडी। भौंती स्थित पीएसआईटी कॉलेज के पास नेशनल हाईवे पर कंटेनर टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खराब खड़े मौरंग लदे डंपर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक उसी में फंस गया। सचेंडी पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह हाईवे पर पीएसआईटी के पास एक कंटेनर रनिया की ओर जा रहा था, इसी दौरान उसका आगे का एक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े डंपर में जा घुसा।

महिला की मौत पर ससुरालियों पर मुकदमा

चकेरी। दहेली सुजानपुर के आदर्श विहार में बीते सोमवार को महिला का शव मिलने के मामले में आरोपित पति समेत ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आदर्श विहार निवासी आशीष गुप्ता की 25 वर्षीय पत्नी स्नेहा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला था। मायके पक्ष ने पति समेत ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पीट–पीटकर हत्या करने का आरोप लगा हंगामा किया था।

शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जली बाइक

कानपुर। फजलगंज स्थित चैन फैक्ट्री चौराहा के पास मंगलवार सुबह एक बाइक की केबल में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंचे फजलगंज के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फजलगंज फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि बाइक सवार युवक जा रहा था। अचानक बाइक की केबल शार्ट होने से धुआं निकलने लगा। युवक बाइक स्टैंड पर लगाकर देखने लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता बाइक जलने लगी।

गोविंदनगर में मोबाइल छीन कर ले भागे किशोर

कानपुर दक्षिण। गोविंदनगर में प्राइवेट कर्मी से दो किशोरों ने एक कॉल कराने के लिए मोबाइल मांगा। पीड़ित ने मोबाइल निकाला तो एक ने धक्का दिया। इसके बाद दोनों मोबाइल लेकर भाग निकले। अवधेश ने बताया कि वह गांधी पार्क मोड़ के पास टहल रहे थे। 13 –14 साल के दो किशोर उनके पास आए और मोबाइल से कॉल कराने को कहा। जेब से फोन निकाला और उनकी ओर बढ़ाया तो उनमें से एक लड़के ने झपट्टा मार कर फोन छीन लिया और दोनों भाग निकले।

युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

कानपुर। महाराजपुर के महुआ गांव निवासी तिलकधारी सिंह की 25 वर्षीय बेटी निशा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन ने बताया कि बीती 11 मई को निशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान मंगलवार को युवती की मौत हो गई।

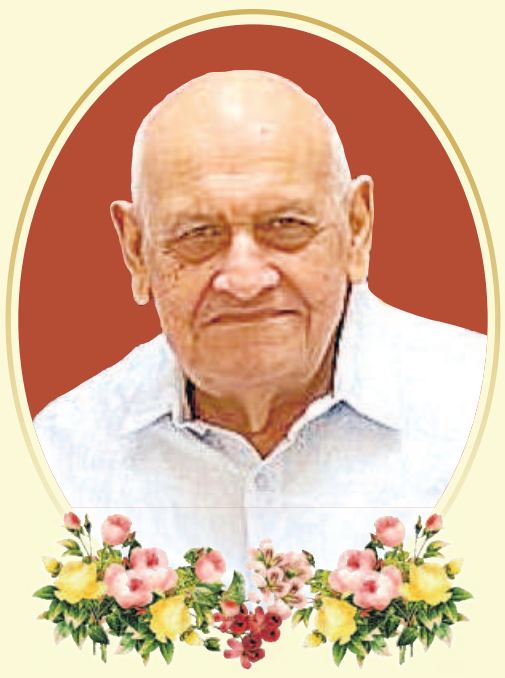

पत्नी ने मायके वालों संग मिल ससुरालियों को पीटा

कानपुर। नवाबगंज स्थित एनआरआई सिटी निवासी अंकित निगम ने अपनी पत्नी पर मायके वालों के साथ मिलकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 2013 में लाल बंगला में रहने वाली अवन्तिका श्रीवास्तव से विवाह हुआ था। पत्नी के गुस्सैल स्वभाव के कारण वह परिवार से अलग फ्लैट में रहते हैं। बीती 17 मई को वह बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पत्नी बेवजह का विवाद करने लगी।